SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारतीय इतिहास में बंगाल विभाजनः एक अवलोकन

जितेन्द्र कुमार, पीएच–डी, इतिहास विभाग
मोलदियार टोला, वार्ड नं.–12, मोकामा, पटना, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author

जितेन्द्र कुमार, पीएच–डी
E-mail : jitendrakumar1531987@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 29/01/2026
Revised on : 31/03/2026
Accepted on : 09/04/2026
Overall Similarity : 08% on 01/04/2026

Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment
8%
Overall Similarity

Date: Apr 1, 2026 (04:06 PM)
Matches: 170 / 2081 words
Sources: 1

Remarks: Low similarity detected, consider making necessary changes if needed.

Verify Report: Scan this QR Code

शोध सार

भारतीय इतिहास में तिरस्कार, मानहानि और धोखा के नाम से प्रसिद्ध 1905 का बंगाल विभाजन राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रथम उत्ताल तरंग था। संयुक्त बंगाल प्रान्त का निर्माण 1773 ई. में किया गया और यह 1905 ई. तक अविभाज्य रहा। 1903 ई. में बंगाल के गवर्नर सर एण्ड्रयू फेजर ने बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा जिसे मूर्तरूप तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिया। वस्तुतः बंगाल विभाजन विलियम बार्ड की दिमागी उपज थी। यह विभाजन कांग्रेस की बढ़ती शक्ति को क्षीण करने, राष्ट्रीय आन्दोलन को कमजोर बनाने तथा भारत में साम्प्रदायिकता को और अधिक फैलाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि हिन्दू और मुसलमान आपस में बँट जाएँ और रोमन कहावत 'बाँटो और राज करो' का नारा भारत में और अधिक दिनों तक कायम रह सके। कलकत्ता उस समय की राजधानी थी, इसी कारण बंगालियों को पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सर्वाधिक और सर्वप्रथम मिला। अतः ये राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हो गए और बंगाल पूरे हिन्दुस्तान की राजनैतिक आन्दोलन का केन्द्र बन गया था। परिणामस्वरूप लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीयता को खंडित करने हेतु मुस्लिम प्रधान पूर्व बंगाल को अलग कर उसे हिन्दूप्रधान शेष बंगाल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की।'

मुख्य शब्द

बंगाल विभाजन, राष्ट्रीय आंदोलन, सम्प्रदायिकता, एसोसिएशन, राष्ट्रीयता, हड़ताल.

भूमिका

बंगाल जो बिहार, असम, बांग्लादेश तथा उड़ीसा तक विस्तृत भाग था, इसका क्षेत्रफल 1,89,00 वर्ग कि.मी. था तथा इसका कुल जनसंख्या 8.5 करोड़ थी। 1903 ई. में लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्व्यवस्थापन का हवाला देते हुए पूर्वी बंगाल तथा असम को एक नया प्रान्त बनाया जिसमें राजशाही, ढाका तथा चटगाँव के तीन डिवीजन शामिल थे। इसका क्षेत्रफल था 1,06,540 वर्ग कि.मी. एवं इसकी जनसंख्या थी 310 लाख, जिसमें 120 लाख हिन्दू थे तथा शेष मुसलमान।

इसका मुख्यालय ढाका बनाया गया। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को मिलाकर एक पृथक प्रान्त बनाया गया, जिसका क्षेत्रफल था 1,41,580 वर्ग कि.मी. तथा इसकी कुल जनसंख्या थी 540 लाख जिसमें 420 लाख हिन्दू थे और 90 लाख मुसलमान। प्रारम्भ में तो वर्ष 1905 तक भारतीयों को इस धोखे में रखा गया कि बंगाल विभाजन की घोषणा त्याग दी गई है, लेकिन अचानक 7 जुलाई 1905 को शिमला में बंगाल विभाजन की सरकारी घोषणा की गई। 20 जुलाई 1905 को विभाजन dhl Eiw.kZ;kstuk çdkf'kr gqbZA 16 vDVwcj ls;g ;kstuk ykxw gksuk fuf'pr gqvkA[2]

बंगाल विभाजन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। इसने बंगाल की राष्ट्रीयता पर कठोर प्रहार किया। हिन्दू तथा मुसलमानों के बीच विभेद की दीवार खड़ी कर दी गई। बंगाल में सम्प्रदायिकता का बीज बोकर कर्जन ने भारत में सबसे पहले पृथक मुस्लिम क्षेत्र बनाने का रास्ता साफ कर दिया। बंगाल विभाजन से गंगा नदी क्षेत्र से विरोध की आग लगाई गई बंगाली अपमानित तथा ठगे से रह गए शिक्षित, प्रबुद्ध एवं देशभक्त बंगालियों ने इसे अपना अपमान समझा तथा अपनी परम्परा, इतिहास, भाषा व संस्कृति पर कुठाराघात माना। इसका बड़ा विरोध हुआ तथा विरोध की पहली शुरूआत विक्रमपुर से हुई। विभिन्न वर्गों के लोगों ने इसका विरोध भिन्न–भिन्न कारणों से किया।[3]

1. सामान्य जनता ने बंगाल विभाजन का विरोध किया, क्योंकि उन्हें अब नौकरी नहीं मिलेगी।
2. व्यापारियों ने चावल उद्योग को ध्यान में रखकर विरोध किया।
3. भू–स्वामियों के विरोध का कारण था कि राज्य के दो भागों में बँटने से उन्हें भूमि सुरक्षा की असुविधा होगी तथा उन्हें दोनों क्षेत्रों में पृथक पदाधिकारी नियुक्त करना होगा।
4. वकीलों के विरोध का कारण था कि दो न्यायालय होने से उन्हें कम काम मिलेगा।
5. राजनीतिज्ञों ने विरोध किया, क्योंकि राजनीतिज्ञों की परिषद् का सदस्य बनने में कठिनाई होती।[4]

वस्तुतः भारतीयों ने उपर्युक्त कारणों के अलावा बंगाल विभाजन का विरोध कर्जन की प्रतिगामी नीति के कारण किया। कर्जन ने बंगालियों की बढ़ती हुई राजनीतिक जागृति को समाप्त करने का यह मार्ग निकाला था। उसने एक निजी एवं गोपनीय पत्र में 17 फरवरी, 1904 को भारत सचिव को लिखा था–''ये बंगाली अपने आपको एक राष्ट्र मानते हैं और वे उस समय का स्वप्न देख रहे हैं जब अंग्रेज यहाँ से निकाल दिए जा चुके होंगे और कलकत्ता के राजभवन में एक बंगाली बाबू बैठा होगा, वे लोग निश्चित ही अपने इस स्वप्न को साकार करने में किसी बाधा को उपस्थित करने की इच्छा नहीं मानते। यदि हमने इस समय तनिक भी शिथिलता दिखाई और उनके शोर से हम पीछे हट गए तो हम बंगाल को पुनः कभी भी जीतने में सफल नहीं होंगे और आप भारत के पूर्व भाग में उन शक्तियों को दृढ़ कर रहे होंगे, जो हमारे लिए भविष्य में निश्चय ही कष्टदायक सिद्ध होगी।''[5] इन्हीं कारणों से कांग्रेस ने 1903 से 1906 तक के प्रत्येक सत्र में बंग–भंग का विरोध किया तथा इसे रद्द करने की मांग की। कांग्रेस के साथ–साथ प्रेस ने भी बंग–भंग पर तीक्ष्ण प्रहार किए।

बंगालियों ने इस विभाजन की तुलना नंद कुमार की फाँसी (वारेन हेसिटंग्स का काल) से की तथा उसी के समान इस आन्दोलन में भी देवी काली के समक्ष शपथ ली गई। बंगाल में लगभग 2000 जनसभाएँ हुई जिसमें लोगों की उपस्थिति 500 से 50,000 तक रही, कलकत्ता के टाउन हॉल में 5 जनसभाएँ हुई, जिसमें संयुक्त बंगाल के हिन्दू, मुसलमान, राजा–महाराजा, नवाब–जमींदार, शिक्षित–अशिक्षित सभी लोग शामिल हुए। ब्रिटिश इण्डिया एसोसिएशन, बंगाल लैंडहोल्डर्स एसोसिएशन तथा अन्य संगठनों ने भी बंग–भंग को रद्द करने की माँग की। 70,000 लोगों के सुक्त हस्ताक्षर का एक आवेदन–पत्र भारत सचिव को भेजा गया। आन्दोलन काफी लोकप्रिय हुआ। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने कहा, ''जिस प्रकार चार्ल्स प्रथम तथा पार्लियामेंट के बीच संघर्ष की कथा इंगलैण्ड के हर घर के चूल्हे तक पहुँची, वही स्थिति बंगाल विभाजन की भी हो गयी है।''[6]

प्रारम्भिक विरोधों के बावजूद यह विभाजन रद्द नहीं किया गया, तो लोगों को यह लगा कि योजना लाद दी गई है। फलतः स्वदेशी व बायकॉट का नारा बुलंद हुआ जिसकी घोषणा कृष्ण कुमार मित्र ने 'संजीवनी' नाम पत्रिका से की। लाल मोहन घोष ने अमृत बाजार पत्रिका में कहा, ''सरकार का साथ देना बंद करें. अवैतनिक मजिस्ट्रेट, जिला बोर्डों तथा पंचायतों के सदस्य एक साथ इस्तीफा दें, साथ ही 12 महीने का राष्ट्रीय शोक मनाया जाए। इसी से संबंधित अनेक सभाएँ–पबाना, फरीदपुर, तगाइल, मगुडा, मैमनसिंह, मानिक गाँव, ढाका आदि स्थानों पर हुई सभी सभाओं में ब्रिटिश माल के बहिष्कार तथा राष्ट्रीयता का नारा बुलंद किया गया। बंगाल भर में बुलंद होने वाले नारों ने नेताओं को आन्दोलन की दिशा–निर्धारण में काफी मदद की। बंग–भंग आन्दोलन में छात्रों की भागीदारी काफी प्रभावशाली रही। 7 अगस्त को लगभग 50,000 छात्रों ने शान्तिपूर्ण ढंग से कतारबद्ध होकर नपे–तुले कदमों से भारी मन काले झण्डे लिए रैलियाँ निकाली। बड़े–बड़े बैनरों पर लिखा था– 'संयुक्त बंगाल',

'एकता ही बल है', 'बन्दे मातरम्', 'बंग–भंग' नहीं चलेगा साथ ही यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि जब तक बंग–भंग रद्द नहीं होगा, आन्दोलन चलता रहेगा। ब्रिटिश माल के बहिष्कार का स्वागत पूरे बंगाल में किया गया। कहीं–कहीं कर्जन के पुतले भी जलाए गए। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बायकॉट किया गया। 16 अक्टूबर, जिस दिन से विभाजन लागू होना था, समीप आ रहा था, आन्दोलन द्विगुणित उत्साह से बढ़ता जा रहा था, छात्रों व शिक्षकों ने नंगे पाँव स्कूल व कॉलेज जाना प्रारम्भ किया। छात्रों के अलावा मोचियों, धोबियों ने भी विदेशी माल का बहिष्कार किया। रवीन्द्र नाथ टैगोर तथा रजनीकांत सेन आदि कवियों ने देशप्रेम की कविताओं के द्वारा आन्दोलनकारियों का जोश बढ़ाया।[7]

28 सितम्बर को पितृ विसर्जन का दिन था, उसी दिन कलकत्ता के कालीघाट मंदिर में अनोखी विराट पूजा हुई, सबेरे से ही नंगे पैर लोग वंदे मातरम् का नारा लगाते हुए कालीघाट की ओर बढ़ने लगे। 50,000 की भीड़ कीर्तन की जगह राष्ट्रीय गीत गा रही थी। 16 अक्टूबर, जिस दिन विभाजन होना था, रवीन्द्र नाथ टैगोर ने बंगाल को मजबूत करने हेतु रक्षाबंधन मनाने की घोषणा की।'[8]

16 अक्टूबर को पूरी हड़ताल हुई। नौजवानों की प्रभात फेरियों वंदे मातरम् गाती निकली। फिर राखी बंधन का कार्य प्रारम्भ हुआ। तीसरे पहल फेडरल हॉल में सभा हुई जिसमें सम्मिलित 60,000 लोगों की अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने की और यहीं पर पूर्ण स्वदेशी आन्दोलन का प्रस्ताव पास किया गया तथा विदेशी बायकॉट और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने का निश्चय किया गया। इस आन्दोलन को सम्पूर्ण बंगाल की जनता ने तो स्वेच्छा से अपना समर्थन दिया ही, बंगाल के बाहर बर्मा, रावलपिंडी, मद्रास, आगरा तथा पुणे आदि जगहों पर भी बंग–भंग विरोध का आन्दोलन चला। कर्जन के द्वारा मुसलमानों को इस आन्दोलन से दूर रखने की पूरी कोशिश के बाद भी काफी संख्या में मुसलमान भी इस आन्दोलन में शामिल हुए। अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, अब्दुल रहीम, गजनवी, यूसूफ बहादुर खान तथा मुहम्मद इसमाइल चौधरी आदि नेताओं ने इस आन्दोलन में जमकर साथ दिया। मुसलमानों की एक बड़ी सभा राजा बाजार में अब्दुल रसूल की सदारत में हुई जिसमें दो प्रस्ताव किए गए[9]:

अ. मुल्क की तरक्की के लिए जो काम हिन्दू करेंगे मुसलमान उसका समर्थन करेंगे।

ब. मुसलमान हिन्दुओं का साथ सिर्फ बंगाल विभाजन के खिलाफ में नहीं, दूसरे मामलों में भी देंगे।

इस प्रकार बंगाल विभाजन विरोधी आन्दोलन का समर्थन सभी वर्गों ने किया। अंग्रेजों की हर कोशिश नाकाम रही और एक झण्डे के तले इतने लोगों ने पहली बार किसी आन्दोलन में भाग लिया। इस आन्दोलन ने लोगों में राष्ट्रप्रेम, सांस्कृतिक मान्यता और भावनात्मक एकता को बढ़ावा दिया। 1906 के वारीसाल सम्मेलन में बोलते हुए अब्दुल रसूल ने कहा, ''पिछले पचास से सौ सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वह हमने महीने में हासिल कर लिया है और हमें यहाँ तक पहुँचाया है बंगाल–विभाजन ने।''[10]

बंग–भंग आन्दोलन का प्रभाव छद्म के रूप में वरदान था। जिस प्रकार इलबर्ट बिल विवाद ने भारत में शक्ति संगठन का अवसर दिया, उसी प्रकार बंगाल विभाजन ने भारतीयों में नैतिक शक्ति का आभास कराया। बंगाल विभाजन राष्ट्रीय आन्दोलन में मील का पत्थर साबित हुआ तथा इसी के अन्तर्गत राष्ट्रीय संग्राम में एकता की जो नई परिभाषा बनी। यह तीन–तीन आन्दोलनों को अपने में समाहित किए हुए था, ये थे स्वदेशी आन्दोलन, बायकॉट आन्दोलन तथा उग्रवादी आन्दोलन। स्वदेशी आन्दोलन के कारण भारत का औद्योगीकरण भारतीयों के द्वारा ही किया जाने लगा। लघु उद्योगों की बाढ़–सी आ गई तथा लोगों में समाजवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। समाजवादी विचारधारा से भारत में मजदूर आन्दोलन की शुरूआत हुई। आत्मनिर्भरता तथा आत्मशक्ति का नारा देश में बुलंद हुआ तथा लोगों में स्वावलम्बन एवं स्वाभिमान की भावना जगी। राष्ट्रीय शिक्षा का सर्वाधिक विकास इसी दौरान हुआ। बंगाल नेशनल कॉलेज, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् एवं बंगाल तकनीकी संस्थान आदि राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई। अनेक बीमा कम्पनियाँ, कपड़ा, मिलें, बैंक तथा चर्म उद्योग आदि को बढ़ावा मिला, कला को भी काफी प्रोत्साहन मिला। अवनीन्द्र नाथ टैगोर और नंदलाल बोस इसी काल के थे। कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा का व्यापक प्रचार हुआ।[11]

निष्कर्ष

बंग–भंग आन्दोलन में साम्प्रदायिकता का जो छिटपुट विकास हुआ उसकी चरम परिणति दिसम्बर 1906 ई० में मुस्लिम लीग की स्थापना के रूप में हुई जिसका गठन बंगाल में ही हुआ। मुसलमानों के एक बड़े भाग में बंगाल विभाजन आन्दोलन में भाग नहीं लिया इसलिए धर्मों के मतभेद होना स्वाभाविक था और इसी के परिणामस्वरूप 1907 ई. में बंगाल में भीषण दंगा

हुआ। राजनीति के खेल में माहिर अंग्रेज इसी की ताक में थे और इन्होंने शीर्घ ही धर्म को राजनीति में प्रवेश करवाकर 1909 ई० के मार्ले–मिण्टो अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। राजनीति में धर्म के प्रवेश की यह घटना भारत को आज तक प्रभावित करती आ रही है। विभिन्न परिस्थितियों के कारण बंगाल विभाजन 1911 ई० को रद्द कर दिया गया, पर भारतीय इतिहास में यह महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई और कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा।

संदर्भ सूची

1. पाल, बी.सी. (1907) *द फ्रीडम मूवमेंट इन बंगाल.* न्यू इंडिया प्रेस, कोलकाता, पृ. 46।
2. सरकार, तनीजा (1984) पोलिटिक्स एण्ड वूमेन इन बंगाल, *द इंडियन इकॉनामिक एण्ड सोशल हिस्ट्री रिव्यू,* वाल्यूम 21, इसू–1, कलकत्ता, पृ. 19।
3. गांगुली, प्रभातचंद्र (1920) *बांलार नारी जागरण.* नेशनल बुक ट्रस्ट, कोलकाता 1920, पृ. 13।
4. मुखर्जी, हीरने (1986) *इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम.* नेशनल बुक एजेंसी, कलकत्ता, पृ. 81।
5. मिश्रा, एन. (1930–1947) *इंडिया ऐनुअल रजिस्टर.* एनुअल रजिस्टर ऑफिस, कलकत्ता।
6. दास, एम. एन. (1959) *द पोलिटिकल एण्ड सोशल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया.* साउथ एशिया बुक्स, कलकत्ता, पृ. 101।
7. शर्मा, एल. पी. (2020) *इंडियन नेशनल मूवमेंट.* लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, पृ. 43।
8. बेसेंट, ऐनी (1916) *इडियाः ए नेशन.* टी.सी. एण्ड ई.सी. जैक प्रकाशन, लंदन, पृ. 73।
9. कुमार, नागेन्द्र (1979) *इंडियन नेशनल मूवमेंट.* जानकी प्रकाशन, पटना, पृ. 81।
10. चन्द्र, विपिन (1920) *आधुनिक भारत का इतिहास (1857–1947).* ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, पृ. 17।
11. शुक्ल, रामलखन (2015) आधुनिक भारत का इतिहास' हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ. 72।

****